Government medical colleges in the country to set up cobalt therapy facilities in a phased manner.

Abolition of octroi by States

*212. SHRI A. G. KULKARNI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the names of the States which have by now abolished the octroi and of those which have not;

(b) whether central guidelines have been issued in this regard to streamline the procedure for collection of municipal dues on vehicles; and

(c) whether Government propose to call a meeting of the State Ministers to sort out the difficulties and adopt a pragmatic policy of Octroi?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT): (a) The Octroi is not levied in—

Andhra Pradesh, Assam, Arunachal Pradesh, Bihar, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Nagaland, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Lakshadweep.

The Octroi is levied in—

Haryana, Jammu & Kashmir, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Gujarat, Goa, Andaman & Nicobar Islands, Delhi, Daman & Diu and Pondicherry.

(b) and (c) The subject matter octroi falls within the purview of States/UT Administrations. The Central Government has repeatedly impressed upon the State Governments/Union Territories to abolish Octroi. The TDC in its meetings has also urged States Govts. to take early action and suggested, for their consideration, alternative source of income like surcharge on sales tax to finance local bodies. In February 1988, a special meeting was also taken with the Lt. Governor/representatives of Administrations. The State Transport Ministers in the ensuing annual meeting of the TDC would be again discussing the matter.

इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता

*213. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (**कुमारी सरोज खापर्डे**) (क) और (ख) इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रो-होम्योपैथी को मान्यता प्रदान करने के लिए कई व्यक्तियों, संघों आदि से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया है जो इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रो-होम्योपैथी की एक वैध वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति के रूप में जांच करेगी। उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय द्वारा आगे की कार्रवाई करने पर विचार किया जाएगा। इलेक्ट्रोपैथी को उपचार की एक पद्धति के रूप में मान्यता प्रदान करने के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

इन्दौर में विमानों के रात में उतरने संबंधी सुविधाएं

*214. **श्री अजीत जोगी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्दौर में विमानों के रात में उतरने संबंधी